रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2015] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939
No. 2015] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 जुलाई, 2017

का.आ. 2273(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 252(अ), तारीख 27 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां या आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

पामेड वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर, में स्थित है और 442.23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य वनस्पति एवं जीवजंतु के विभिन्न प्रजातियों के समृद्ध प्राकृतिक वास के लिए प्रसिद्ध है। महत्त्वपूर्ण वनस्पति में सागौन (*टेक्टोना ग्रैंडिस*), शीशम (*डाल्बर्गिया लैटिफ़ोलिया*), कुसुम (*श्लेकेचरा ऑलिओसा*), महुआ (*मधुका इंडिका*), तेंदु (*डायस्पिरोस मेलेनोक्सिलॉन*), बांस (*डेन्ड्रोकालेमास कडक*), आदि हैं। अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण जीवजंतु तेंदुआ (*पेंथेरा पार्दस*), नीलगाय (*बोसेलफस ट्रागोकैमेलस*), सांभर (*रूसा यूनीक्लोरर*), बनैला सूअर (*सूस स्क्रोफा*), जंगली कुत्ता (*लाइकाओन पेक्टस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस सिलवेस्टिस*), मोर (*पावो क्रिस्टटस*), लंगूर, लघु पुच्छ वानर (*मैकाक एसपी.*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), रीछ (*मेलुस यूरसीन्स*), साही (*हाइस्ट्रीक्स इंडिका*), सियार (*कैनिस ऑरियस*) इत्यादि हैं। अभयारण्य उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन,

उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, शुष्क सदाबहार वन, और जलीय वनस्पति से मिलकर बना है। अभयारण्य इन्दरावती व्याघ्र रिजर्व के लिए प्राकृतिक आवास के विस्तार की भी व्यवस्था करता है ।

और, पामेड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 मीटर से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पामेड वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन अक्षांश 18° 26' 04" उ० से 18° 11' 31" उ० और 80° 43' 57" पू० से 81° 03' 57" पू० देशांतर के बीच स्थित है। अभयारण्य के पश्चिमी दिशा के हिस्से को छोड़ते हुए, जिसकी सीमा तेलंगाना राज्य के साथ मिलती है, पामेड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के विस्तार के साथ 62.73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) भू-निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को विभाजित करते हुए पामेड वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है ।

(3) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) इस प्रकार तैयार की गई आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप होगी और उसमें पर्यावरणीय विवक्षाएं शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग ।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर तब तक कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप के सुधार में कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किए गए ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल के प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कबीले क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, दलदली जमीन, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इसके साथ समर्थनकारी मानचित्र भी होगा योजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित तथा संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सकें। ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं होगा या उनके लिए क्षेत्रों में संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उन्हें मजबूत करना ;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
(iv) वर्षा जल संचयन; और
(v) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक और उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परन्तु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषिक्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजनाएं आचंलिक महायोजना सम्मिलित की जाएंगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसी क्षेत्र आवाह संबंध योजना ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जिससे आवाह क्षेत्रों के भीतर विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित किया जा सके ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पामेड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, नए होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन पर जोर देते हुए मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और परिरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य तथा ऐतिहासिक पुरातत्वीय, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करेगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुबंधित उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को क्रियान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए विनियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- बहिस्रावों का निस्सारण पारिस्थितिक जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निर्वहन के लिए साधारण मानकों के उपाबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का पारिस्थितिक संवेदी जोन बाह्य पहचान की गई स्थल पर पर्यावरण स्वीकार्य रीति में व्ययन किया जाएगा ;

(iii) ठोस अपशिष्टों के ज्वलन या भस्मीकरण और भराई के स्थापना को पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञा नहीं की जाएगी ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में पहले से ही व्यक्तिगत अस्पतालों या निजी स्वास्थ्य केंद्रों के संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल असर से बचने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत नियमों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन की निगरानी करेगी ।

(15) **औद्योगिक इकाइयां: -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुमति विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों की दी जाएगी अन्यथा नहीं।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(16) यदि यह आवश्यक समझा जाए, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर का उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध की जाती हैं जिसमें मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलों या ईटों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) सभी खनन संक्रियाएं 1995 की रिट याचिका (सी) सं. 202 में टी एन गोदा वर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में और 2010 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ

		के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और आदेश तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अनुसार की जाएंगी ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण, इत्यादि कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वाले विद्यमान उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों जिनके अंतर्गत कीटनाशी और कीटनाशक का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रालाइट, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा । परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
10.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा अनुज्ञात नहीं होगी । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापना/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अतिरिक्त संस्थापन प्रतिषिद्ध है ।
11.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
13.	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिलेटों और	लागू विधियों के अनुसार विनियमित। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिलेटों

IndiaCode

	टेट्रापैकों का उपयोग ।	और टेट्रापैकों का निपटान सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा ।
14.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
15.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलामीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने की भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में गृह वास सहायक हो; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए ही सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण जिसके अंतर्गत वह भाग मात्रा जिसका निष्कर्षण किया जा सकती है के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
18.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यमान सिरोपरि विद्युत केबलों को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर

	अन्य बुनियादी ढांचे ।	विद्युतरोधी बनाया जाएगा।
19.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार, न्यूनीकरण के उपायों के साथ, लागू विधियों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित उपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा जिसमें जल निकायों में जल प्रवेश न करे । उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के निस्सारण को विनियमित किया जाएगा।
25.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।(एन.टी.एफ.पी.)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि प्रणाली में भारी बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	खुले कुंआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित होंगे और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरी, पशुपालन कृषि जलकृषि और मछली पालन ।	स्थानीय निवासियों के उपयोग कि लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
34.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	निम्नीकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) प्रभागीय आयुक्त, जगदलपुर - अध्यक्ष ;

(ख) कलक्टर, जिला बीजापुर– सदस्य ;

(ग) उप निदेशक, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, बीजापुर- सदस्य;

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर - सदस्य;

(ङ) अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर – सदस्य ;

(च) अधीक्षण इंजीनियर, जन स्वास्थ्य इंजीनियरी, जगदलपुर – सदस्य ;

(छ) तीन वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र में एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव या सदस्य -सदस्य;

(झ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि– सदस्य;

(ञ) नगर और ग्राम्य योजना विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(ट) छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि– सदस्य ;

(ठ) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और परियोजना निदेशक, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, जगदलपुर -सचिव। – सदस्य

निर्देश निबंधन -

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) मानीटरी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण संजात निर्धारण, 2006 का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा और तटीय विनियमन जोन का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 और इनमें किए गए पश्चात्वर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत भी आते हैं जिनके अंतर्गत इसके

पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी हैं । श्वेत प्रवर्ग के उद्योगों पर "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, उनके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगी ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में संलग्न रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उनके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

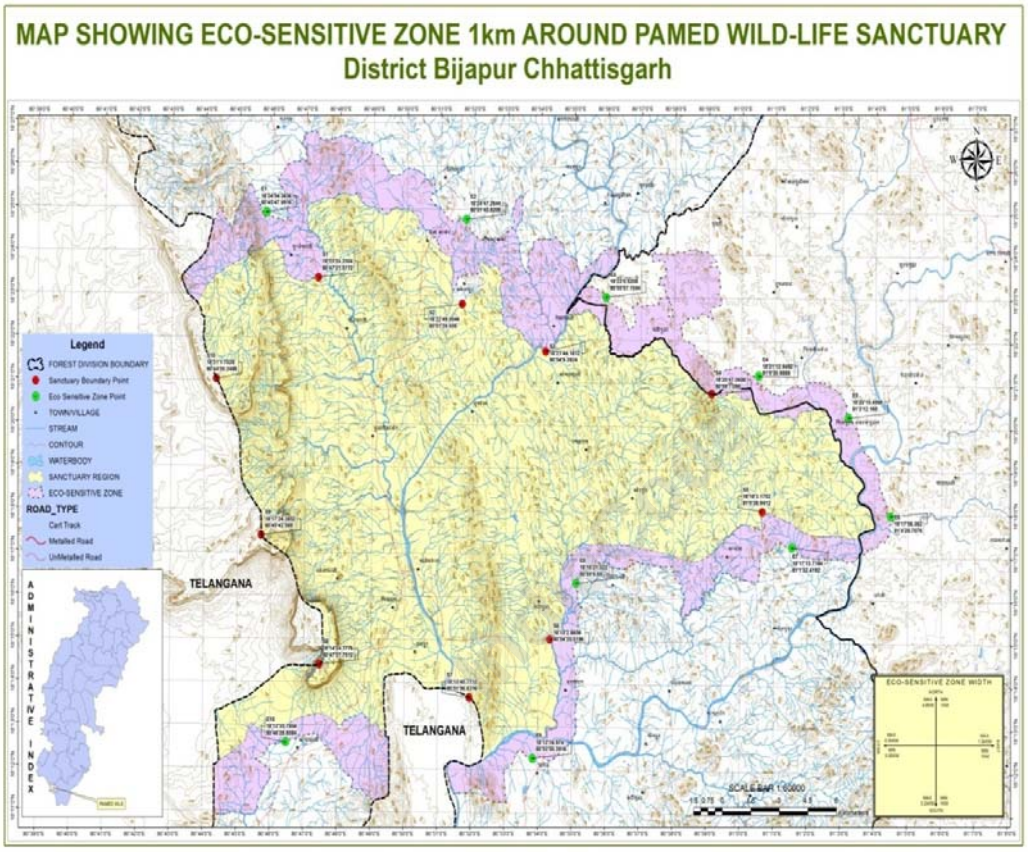
8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/152/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ पामेड वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध I(क)

पामेड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश(डीएमएस)	देशांतर(डीएमएस)
1	एस1	18°23'24.2304	80°47°21.5772
2	एस 2	18°22'49.0044	80°51°39.456
3	एस 3	18°21'44.1612	80°54°9.3924
4	एस 4	18°20'47.0688	80°59°7.098
5	एस 5	18°18'3.1752	81°0°38.9412

6	एस 6	18°15'2.8656	80°54°20.0196
7	एस 7	18°13'40.7712	80°51°56.6316
8	एस 8	18°14'24.7776	80°47°27.7512
9	एस 9	18°17'24.3852	80°45°42.588
10	एस 10	18°21'1.7028	80°44°20.2488

पामेड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश(डीएमएस)	देशांतर(डीएमएस)
1	ई1	18'24'54.3636	80'45'47.9916
2	ई2	18'24'47.2644	80'51'45.8208
3	ई3	18'23'0.5208	80'55'57.1044
4	ई4	18'21'12.9492	81'0'30.9888
5	ई5	18'20'15.4968	81'3'12.168
6	ई6	18'17'58.362	81'4'28.7076
7	ई7	18'17'13.7184	81'1'32.4192
8	ई8	18'16'21.522	80'55'6.69
9	ई9	18'12'16.974	80'53'50.3916
10	ई10	18'12'35.7804	80'46'28.8084

IndiaCode

उपाबंध-II

पामेड वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	अक्षांश-डीएमएस	देशांतर-डीएमएस
1	भाटीगुडा	18°22'9.516	80°57'25.8084
2	कमलापुर	18°23'21.1812	80°51'47.4516
3	कोटापाल्ले	18°12'28.4904	80°46'46.668
4	मरुदबाका	18°24'6.9984	80°52'10.254
5	नम्बी	18°24'3.6432	80°46'34.5504
6	नेलाकाकेर	18°24'29.3472	80°51'4.8564
7	रेखापल्ली	18°22'21.7056	80°54'25.344

IndiaCode

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 19th July, 2017

S.O. 2273(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 252 (E), dated 27th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments/objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Pamed Wildlife Sanctuary is situated in Bizapur District of Chhattisgarh and is spread over an area of 442.23 square kilometres. The Sanctuary is known for its rich varieties of flora and fauna. Important flora includes Teak (*Tectona grandis*), Sisham (*Dalbergia latifolia*), Kusum (*Schleichera* oleosa), Mahua (*Madhuca indica*), Tendu (*Diospyros melanoxylon*), Bamboo (*Dendrocalamus strictus*), etc. The fauna of the sanctuary includes Leopard (*Panthera pardus*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Sambhar (*Rusa unicolor*), Wild boar (*Sus scrofa*), Wild dog (*Lycaon pictus*), Wild Cat (*Felis silvestris*), Peacock (*Pavo cristatus*), Langur, Macaque Monkey (*Macaque sp.*), Chital (*Axis axis*), Sloth Bear (*Melusus ursinus*), Porcupine (*Hystrix indica*), Jackal (*Canis aureus*), etc. The sanctuary is composed of tropical moist mixed deciduous forest, tropical dry deciduous forest, mixed forest, dry evergreen forest, and aquatic vegetation. The sanctuary also provides an extension of habitat to Indrawati Tiger Reserve.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pamed Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 metres to 1 km around the boundary of Pamed Wildlife Sanctuary in the State of Chhattisgarh as the Pamed Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco sensitive Zone lies between 18^0 26' 04" N to 18^0 11' 31" N Latitudes and 80^0 43' 57" E to 81^0 03' 57" E Longitudes. The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 62.73 square kilometers with an extent of 1 km around the boundary of Pamed Wildlife Sanctuary excluding portion on the Western side of the Sanctuary which shares boundary with the State of Telangana.

(2) The map of Pamed Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary along with the geo co-ordinates are appended as **Annexure I**.

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final

notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Chhattisgarh State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department.

IndiaCode

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village artisans.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Chhattisgarh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Chhattisgarh.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Pamed Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

IndiaCode

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**- Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone;

(ii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone should provide adequate waste treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E- waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

IndiaCode

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the ESZ Area by aircraft, hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste are permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
12.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
13.	Use of plastic carry bags, laminates and	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic

IndiaCode

	tetra packs.	articles, laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
14.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
15.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as.- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this notification.
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can

IndiaCode

		be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	The existing overhead electric cables shall be insulated within a specified period as per the Zonal Master Plan. Underground cabling may be promoted.
19.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
29.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
30.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
34.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
40.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) Divisional Commissioner, Jagdalpur- Chairman;

(b) Collector, Bijapur Distict- Member;

(c) Deputy. Director, Indravati National Park, Bijapur- Member;

(d) Chief Executive Officer, District Panchayat, Bijapur- Member;

(e) Superintendent Engineer PWD, Jagdalpur- Member;

(f) Superintendent Engineer PHE, Jagdalpur - Member;

(g) One expert in ecology to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of three years- Member;

(h) Member-Secretary or Member, Chhattisgarh State Biodiversity Board– Member;

(i) Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of three years- Member;

(j) Representative of the Town and Country Planning Department- Member;

(k) Representative of Chhattisgarh Pollution Control Board- Member;

(l) Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Project Director, Indrawati National Park, Jagdalpur- Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

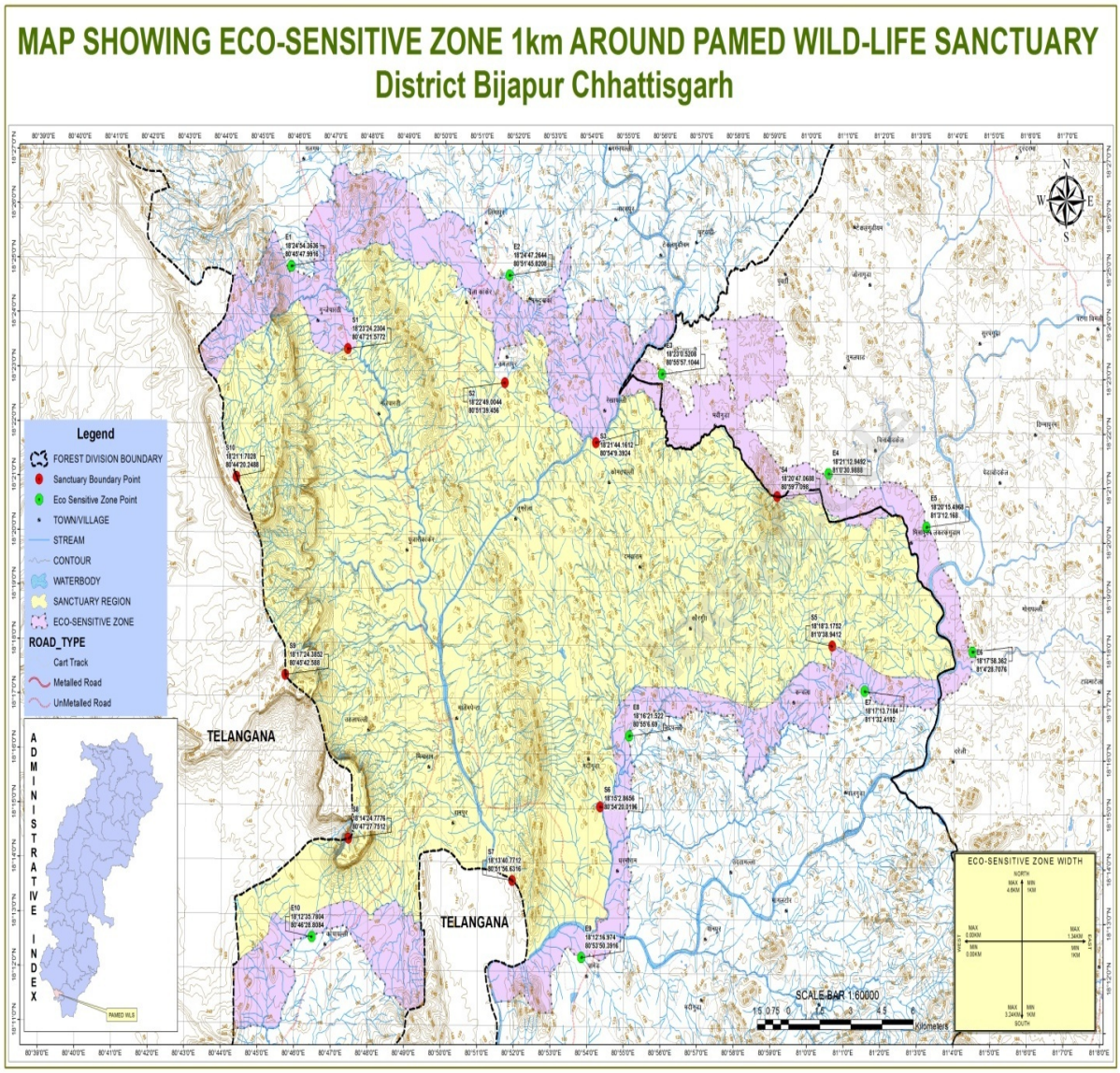
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/152/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Pamed Wildlife Sanctuary along with its Eco- Sensitive Zone



Annexure I (A)

Geo Co-ordinates of Boundary of Pamed Wildlife Sanctuary

S.N.	Reference Point No.	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	S1	18°23'24.2304	80°47°21.5772
2	S2	18°22'49.0044	80°51°39.456
3	S3	18°21'44.1612	80°54°9.3924
4	S4	18°20'47.0688	80°59°7.098
5	S5	18°18'3.1752	81°0°38.9412
6	S6	18°15'2.8656	80°54°20.0196

7	S7	18°13'40.7712	80°51°56.6316
8	S8	18°14'24.7776	80°47°27.7512
9	S9	18°17'24.3852	80°45°42.588
10	S10	18°21'1.7028	80°44°20.2488

Geo Co-ordinates of Boundary of Eco-Sensitive Zone of Pamed Wildlife Sanctuary

S.N.	Reference Point No.	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	El	18'24'54.3636	80'45'47.9916
2	E2	18'24'47.2644	80'51'45.8208
3	E3	18'23'0.5208	80'55'57.1044
4	E4	18'21'12.9492	81'0'30.9888
5	E5	18'20'15.4968	81'3'12.168
6	E6	18'17'58.362	81'4'28.7076
7	E7	18'17'13.7184	81'1'32.4192
8	E8	18'16'21.522	80'55'6.69
9	E9	18'12'16.974	80'53'50.3916
10	E10	18'12'35.7804	80'46'28.8084

IndiaCode

Annexure II

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Pamed Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh

Sl. No.	Village Name	Lat_DMS	Long_DMS
1	Bhattiguda	18°22'9.516	80°57'25.8084
2	Kamalapur	18°23'21.1812	80°51'47.4516
3	Kottapalle	18°12'28.4904	80°46'46.668
4	Marudbaka	18°24'6.9984	80°52'10.254
5	Nambi	18°24'3.6432	80°46'34.5504
6	Nelakaker	18°24'29.3472	80°51'4.8564
7	Rekhapalli	18°22'21.7056	80°54'25.344

Annexure-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record; Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; Details may be attached as separate Annexure
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.21 22:52:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.